डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2015-17

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

● वर्ष 61 ● अंक 01 ● भोपाल ● 1-15 जून, 2017 ● पृष्ठ 8 ● एक प्रति 7 रु. ● वार्षिक शुल्क 150/- ● आजीवन शुल्क 1500/-

ग्लोबल स्किल समिट 1 जून को भोपाल में

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने तैयारियों की समीक्षा की

भोपाल। ग्लोबल स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट समिट-2017 भोपाल में आगामी एक जून को आयोजित होगी। समिट में कौशल विकास और रोजगार पर केन्द्रित 6सेमिनार होंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में इस समिट की तैयारियों की समीक्षा की। समिट में केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्यमंत्री श्री राजीव प्रताप रूड़ी और उद्योग जगत के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रोजगार के नये अवसर की सृजन की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण समिट है। इस महत्वपूर्ण आयोजन की सभी तैयारियाँ समय-सीमा में पूरी करें। समिट में 437 इंटेंशन टू एम्प्लॉय होंगे, जिनके माध्यम से तीन लाख 17 हजार 451 रोजगार का सृजन होगा। समिट में 214 इंटेंशन टू स्किल होंगे, जिनके माध्यम से 2 लाख 22 हजार 816व्यक्ति का कौशल विकास किया जायेगा। बैठक में बताया गया कि समिट के दौरान जिन विषयों पर सेमिनार आयोजित होंगे उनमें विनिर्माण क्षेत्र में कौशल विकास और रोजगार के अवसर, रोजगारोन्मुखी उच्च शिक्षा, स्व-रोजगार के अवसर, कुशल जनशक्ति की भर्ती में अवसर और चुनौतियाँ, महिलाओं के लिये कौशल उन्नयन एवं रोजगार तथा पर्यटन क्षेत्र में कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर शामिल हैं। समिट में कौशल विकास के लिये विभिन्न एम.ओ.यू. होंगे। समिट में लगभग 1500 प्रतिनिधि के अलावा कौशल विकास क्षेत्र के प्रमुख सलाहकार, शैक्षणिक संस्थानों के निदेशक, बैंकिंग क्षेत्र के प्रतिनिधि, नियोजनकर्ता एजेंसियाँ, युवा सशक्तिकरण के लिये काम कर रहे प्रमुख एनजीओ शामिल होंगे।

बैठक में राज्य रोजगार निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष श्री हेमन्त देशमुख, मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिवद्वय श्री अशोक वर्णवाल और श्री एस.के. मिश्रा, प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग श्री मोहम्मद सुलेमान सहित संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

लक्ष्य के पार पहुंचा तेंदूपत्ता संग्रहण

संग्रहण अभी है जारी

भोपाल। प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्रहण ने अपने निर्धारित लक्ष्य को पार कर लिया। संग्रहण लक्ष्य 22 लाख के विरुद्ध अब तक 22 लाख 5 हजार 998मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहीत किया गया है। तेंदूपत्ते का संग्रहण अभी जारी है। लगभग 16हजार फड़ के माध्यम से 33 लाख संग्राहक तेंदूपत्ता संग्रहीत कर रहे हैं।

जिला वनोपज यूनियन मुरैना ने 132 प्रतिशत, झाबुआ 126, नीमच 119, सिंगरौली 115, उज्जैन 113, दक्षिण शहडोल, शिवपुरी, उत्तर पन्ना एवं दक्षिण सागर 111-111, उत्तर सिवनी, सीधी एवं पूर्व मण्डला 109-109, विदिशा, इंदौर, अशोकनगर, गुना एवं अनूपपुर 103-103, उमरिया 102, डिण्डोरी 101 तथा सतना, दक्षिण सिवनी और मण्डला में अब तक 100-100 प्रतिशत तेंदूपत्ता संग्रहण किया गया है। संग्राहकों को 1250 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से पारिश्रमिक का प्रति सप्ताह ई-भुगतान किया जा रहा है।

इस वर्ष महुआ फूल खरीदी दर 14 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये प्रति किलोग्राम होने से संग्रहण और संग्राहकों की आमदनी में काफी वृद्धि हुई है। अब तक 1189 संग्रहण केन्द्र पर 47 हजार 722 क्विंटल महुआ फूल की खरीदी की गयी है। इसके एवज में संग्राहकों को 14 करोड़ 31 लाख 59 हजार का भुगतान किया गया है। सर्वाधिक महुआ खरीदी 24 हजार 474 क्विंटल शहडोल संभाग में हुई है।

भूटान आर्मी के जूनियर आफीसर्स के प्रशिक्षण सत्र का समापन

श्री सारंग सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने कोर्स कम्पलीशन सर्टिफिकेट दिये

भोपाल। भूटान रॉयल आर्मी और भूटान रॉयल गार्ड के लिए 27 फरवरी, 2017 से प्रारंभ होकर तीन महिने तक सहकारी प्रबन्ध संस्थान, भोपाल में चले प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन श्री विश्वास सारंग सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा प्रमाण पत्र के वितरण के साथ पूरा हुआ। श्री सारंग ने विश्वास जताया कि लघु उद्योग और उद्यमिता विकास पर प्रशिक्षित होने के बाद भूटान आर्मी के जूनियर कमीशन आफीसर्स अपनी सेवाकाल पूरा होने के बाद कोई लघु उद्योग खोल सकेंगे।

मंत्री महोदय ने उपस्थित जूनियर आफीसर्स और सहकारिता विभाग के अधिकारियों को बताया कि भूटान द्वारा सेना के अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए भोपाल में भेजा जाना राज्य के प्रति और राज्य के सहकारिता के प्रति एक सम्मान का सूचक हैं। इससे प्रदेश की सहकारी प्रशिक्षण व्यवस्था की ख्याति विदेशों तक पहुचेंगी। उन्होंने आशा जतायी कि भविष्य में भी सहकारी प्रबन्ध संस्थान, भोपाल इस तरह के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करेगा। उन्होंने इस कार्यक्रम के उद्देश्यों की सराहना करते हुए कहा से खुद के साथ दूसरों के लिए भी रोजगार पैदा हो सकते हैं जो कि आज के समय की मांग हैं।

शेष पृष्ठ 2 पर

ई-गवर्नेंस की प्रभावी पहल 'प्रगति' ऑनलाइन

मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा दस बड़ी निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा

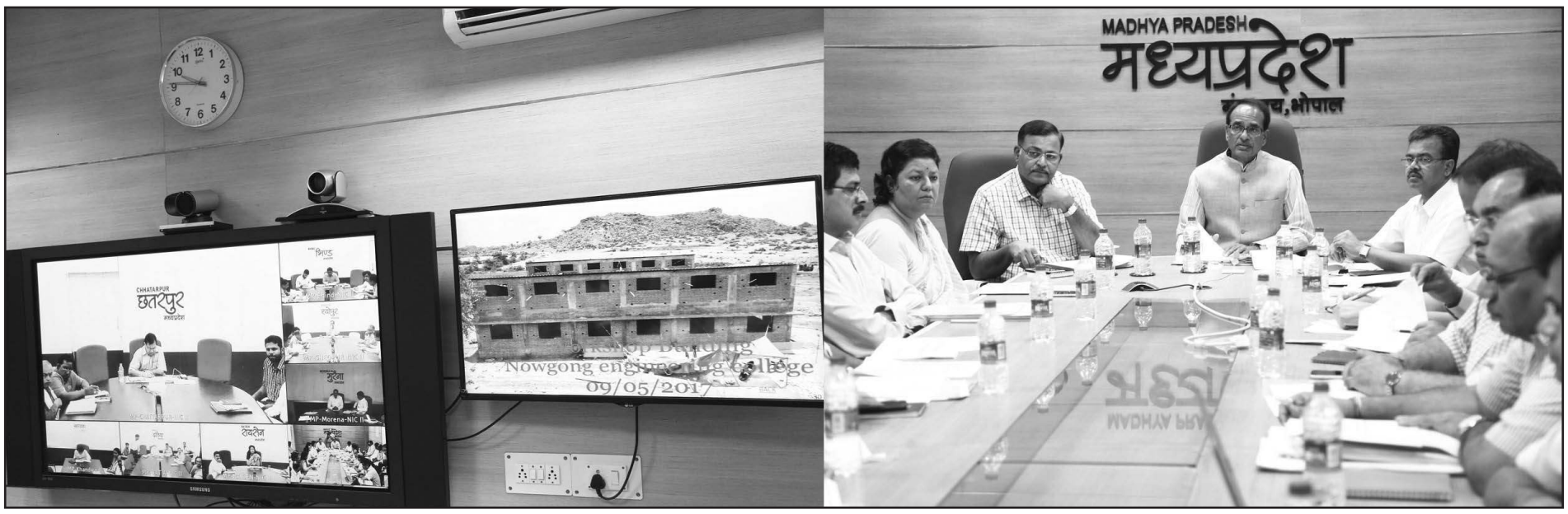

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रगति ऑनलाइन कार्यक्रम में वीडियों कान्फ्रेंस के माध्यम से प्रगतिरत 10 बड़ी परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण, जल संसाधन, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और राजस्व विभाग के कार्यों की परियोजनावार जानकारी ली। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री बी.पी.सिंह भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि परियोजनाएँ समय-सीमा में पूरी हों। उनकी नियमित मॉनीटरिंग की जाये। विलंब करने वाली एजेंसियों के खिलाफ दण्ड के प्रावधान किये जायें। निर्माण से संबद्ध काम भी समानांतर किये जायें। उन्होंने जल प्रदाय योजनाओं के निर्माण से प्रभावित सड़कों को वर्षा ऋतु से पहले अनिवार्यत: दुरूस्त करवाने के निर्देश दिये।

कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की 230 करोड़ रूपये से अधिक लागत की मरदानपुर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना जिला सीहोर, 155 करोड़ रूपये से अधिक की उदयपुरा ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना जिला रायसेन की समीक्षा की। तकनीकी शिक्षा विभाग के नौगाँव छतरपुर में 20 करोड़ रूपये से अधिक लागत के निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कॉलेज निर्माण की जानकारी ली। चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत 175 करोड़ रूपये से अधिक लागत की चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा की अद्यतन प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री को बताया गया कि वर्ष 2018जनवरी तक परियोजना का काम पूरा हो जायेगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा छतरपुर में 32 करोड़ रूपये से अधिक लागत के 300 बिस्तर वाले अस्पताल निर्माण प्रगति की समीक्षा में बताया गया कि निर्माण कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जायेगा। नगरीय विकास तथा आवास विभाग द्वारा बताया गया कि पुनर्घत्वीकरण योजना में रीवा में 18करोड़ रूपये से अधिक लागत के ऑडिटोरियम एवं उपकुलपति निवास निर्माण का काम समय-सीमा में पूरा हो जायेगा।

मुख्यमंत्री को समीक्षा के दौरान जल संसाधन की वृहद परियोजना बानसुजारा के बारे में बताया गया कि 1768करोड़ रूपये से अधिक लागत की योजना से 186 गाँवों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। राजस्व विभाग की ई-भूलेख योजना की समीक्षा में बताया गया कि 32 जिलों की 210 तहसीलों में योजना लागू हो गई है। एप्लीकेशन से प्रतिलिपियों का वितरण किया जा रहा है। कुल 10 करोड़ 41 लाख रूपये का राजस्व अर्जित हुआ है। कुल 17 में से 9 मॉड्यूल पूरे हो गये है, शेष का जून अंत तक पूरा हो जाना अनुमानित है। प्रगति ऑनलाइन में वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग द्वारा विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड नरवर, उज्जैन में 442 हेक्टेयर क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे के विकास का काम किया जा रहा है। वर्ष 2018के अंत तक इसका पूरा हो जाना अनुमानित है। इसमें ऑटो कंपोनेंट, आई.टी., इंजीनियरिंग सर्विसेज एनर्जी हब, मेडिकल हब, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हब विकसित करने का लक्ष्य है। बताया गया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा चंबल एक्सप्रेस-वे का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 552 पर पाली के समीप से शुरू होगा। परियोजना के लिये लगभग 2500 हेक्टेयर भूमि में से 80 प्रतिशत से अधिक शासकीय भूमि उपलब्ध है।

पृष्ठ 1 का शेष

भूटान आर्मी के जूनियर आफीसर्स के प्रशिक्षण सत्र का समापन

संस्थान के निदेशक डॉ. ए. के. अस्थाना ने बताया कि यह संस्थान के इतिहास में पहला मौका है जब भारत के मित्र देश भूटान की आर्मी के जवान प्रशिक्षण लेने के लिए सहकारी प्रबन्ध संस्थान में आये हैं। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य भूटान के सामाजिक और आर्थिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए इन आफीसर्स को स्व रोजगार आधारित उद्योग लगाने के लिए मानसिक तौर पर तैयार करना और आवश्यक जानकारी देना था। ये जवान 40 से 45 वर्ष की आयु वर्ग से हैं। सेना में काम करने के दौरान अनुशासन, समय परखता, आदेश का पालन करना, लक्ष्य की पूर्ति, समय सीमा के अन्दर काम करना, स्वयं का ध्येय निर्धारित करना और काम की सफलता के लिए पूर्ण वफादारी निभाना जैसे गुण इनके व्यक्तित्व मे आ जाते हैं जो इन्हें एक आदर्श मानव संसाधन बनाते हैं। प्रशिक्षण के दौरान अधिकांश आफीसर्स ने डेयरी उद्योग, मुर्गी पालन उद्योग, सब्जी की खेती और बिक्री, व्यावसायिक फूलों की खेती और बिक्री, पॉली हाउस के द्वारा खेती, मशरुम की खेती, जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण लिया।

व्यवहारिक ज्ञान के लिए इन्हें नवीबाग स्थित राष्ट्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, में ले जाया गया। इसके अलावा कृषि विकास केन्द्र, रायसेन के विशेषज्ञों से महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई गई। प्रशिक्षण के दौरान इन्होंने हिन्दी भाषा भी रुचि के साथ सीखी। विदेशों से आये इन मेहमान प्रशिक्षार्थियों को राज्य की उत्कृष्ट संस्थाएँ, सांस्कृतिक विरासत से भी अवगत कराया गया। इस दौरान इन्हें सांची स्तूप, भीम बेटका, इन्दिरा गांधी मानव संग्रहालय , शौर्य स्मारक, भोजपुर मंदिर, भारत भवन, का भ्रमण कराया गया, जिससे उन्हें राज्य की समृद्ध विरासतो को नजदीक से समझने का मौका मिला। इसके अलावा राज्य भवन, विधान सभा और नाबार्ड के उच्च अधिकारियों से रुबरु भेंट कराई गई और उन्हें इन संस्थाओं की गतिविधियों के बारे में बताया गया। रेडियो मिर्ची, भोपाल और आकाशवाणी भोपाल ने भोपाल प्रवास के दौरान उनके अनुभवों को साझा किया।

पी.जी.डी.सी.ए. मात्र 9100/-
डी.सी.ए. मात्र 8100/-
न्यूनतम योग्यता पी.जी.डी.सी.ए.
स्नातक एवं डी.सी.ए.-बारहवीं (10+2)

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित
सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध
प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल
(माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध)
ई-8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल (म.प्र.) पिनकोड-462 039
फोन.-0755 2725518, 2726160 फेक्स-0755 2726160
Email: rajyasanghbpl@yahoo.co.in,ccmtcbpl@rediffmail.com

कपिलधारा कुएँ बने गरीब किसानों की ताकत

मध्यप्रदेश में साढ़े तीन लाख से अधिक कुएँ निर्मित

भोपाल। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, मनरेगा से बनाये गये कपिलधारा कुओं से मध्यप्रदेश के गरीब किसानों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। अब कपिलधारा कुँए इन गरीब किसानों की ताकत बन गए है। सिंचाई के ठोस इंतजाम से साल में तीन फसल के उत्पादन ने इनकी आमदनी कई गुना बढ़ा दी है। प्रदेश के गरीब किसानों की निजी भूमि में सिंचाई सुविधा के लिए बनाये गये कपिलधारा कुओं से किसान अपने खेतों में साल में दो से तीन फसल, बागवानी तथा सब्जियों के उत्पादन का लाभ ले रहे हैं। भरपूर फसल उत्पादन से किसानों की सालाना आमदनी में कई गुना इजाफा हुआ है। अब तक तंगहाली में गुजर-बसर करने वाले बेहतर जीवन-यापन कर रहे हैं।

मध्यप्रदेश में मनरेगा योजना प्रारंभ से अब तक गरीब किसानों की असिंचित जमीन पर लगभग 3 लाख 57 हजार 522 से अधिक कपिलधारा कुओं का निर्माण किया जा चुका है। जिससे 4 लाख 74 हजार 425 हेक्टेयर असिंचित रकबा सिंचित रकबे में तब्दील हुआ है। कपिलधारा कुओं की बदौलत अभी तक बंजर रहने वाली जमीन हरी-भरी होकर विभिन्न किस्म के अनाज, फल, सब्जियों आदि का उत्पादन कर रही हैं।

मनरेगा की कपिलधारा योजना गरीब किसानों की गरीबी दूर करने और उनके जीवन में खुशहाली लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रदेश के ऐसे गरीब किसान जिनके पास खुद की जमीन तो थी पर सिंचाई का साधन न होने की वजह से बरसाती फसल भर ले पाते थे। जिससे उनके साल भर खाने का जुगाड़ भी नहीं हो पाता था। मजबूरन इन किसानों को मजदूरी कर घर का गुजारा करना पड़ता था। मनरेगा ने ऐसे किसानों की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दी। मनरेगा की कपिलधारा योजना से किसानों की जमीन पर सिंचाई की सुविधा के लिए कुओं का निर्माण कराया गया। जिससे उन्हें दोहरा फायदा हुआ, एक तो कूप निर्माण के दौरान काम करने की मजदूरी मिली और सिंचाई का पक्का इंतजाम भी हो गया।

जिन हितग्राहियों को कपिलधारा कूप का लाभ मिला है, वे अब साल में दो से तीन फसलों के साथ-साथ सब्जियों तथा फलों का उत्पादन लेने लगे हैं। सिंचाई की सुविधा होने से साल भर खेती कर पा रहे हैं, दूसरों के खेतों में काम करने वाले अब दूसरों को काम देने लगे हैं। उनकी जमीन पर भरपूर फसल होने से साल भर खाने की जुगाड़ के साथ अतिरिक्त आमदनी बढ़ी है। अब उनके बच्चों की पढाई अच्छी तरह से होने लगी है, जीवन स्तर और रहन-सहन पहले की तुलना में बेहतर हुआ है। ऐसे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने से सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ी है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में जरूरतमंद गरीब किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आगामी पाँच वर्ष में ढाई लाख कपिलधारा कुँए निर्मित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रशिक्षार्थी सीखने के उद्देश्य से प्रशिक्षण प्राप्त करें

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर में प्रबंध संचालक श्री रंजन का उद्बोधन

जबलपुर। प्रशिक्षण ज्ञान का परिमार्जन होता है। प्रशिक्षण केवल प्रमाण पत्र मिलने के उद्देश्य से नहीं वरन् ज्ञान प्राप्त करने के लिये होना चाहिए और वो भी पूरे उत्साह से। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। किसी भी उम्र में हम सीख सकते हैं। पूरे प्रयास और परिश्रम से प्राप्त प्रशिक्षण हमें ज्ञानवान बनाता है और अपने कार्यक्षेत्र में सफलता भी देता है।

ये विचार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्या. भोपाल के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन ने जबलपुर प्रवास के दौरान सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर में आयोजित सहकारी प्रबंध में उच्चतर पत्रौपाधि पाठ्यक्रम (HDCM) सत्र क्रमांक 15 के प्रशिक्षार्थियों को भेंट देते हुए व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षार्थियों को संकल्पबद्ध होकर लाभ उठाना चाहिए ताकि ये प्रशिक्षण उनके लिये सार्थक सिद्ध हो। प्रबंध संचालक महोदय ने प्रशिक्षार्थियों के प्रति हार्दिक शुभकामनायें व्यक्त करते हुए उनका परिचय प्राप्त किया और राज्य सहकारी संघ के शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की भी विस्तृत चर्चा की।

कार्यक्रम के प्रारम्भ में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक ने स्वागत भाषण देते हुए केन्द्र की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर केन्द्र की ओर से प्राचार्य के स्टाफ ने प्रबंध संचालक श्री रंजन साहब का पुष्पहार से स्वागत करते हुए सम्मान पत्र भी भेंट किया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए केन्द्र जबलपुर के व्याख्याता श्री शशिकांत चतुर्वेदी ने केन्द्र में एच.डी.सी.एम. की उपयोगिता पर प्रकाश डाला एवं प्रशिक्षण के विषयों की जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन केन्द्र जबलपुर के प्रशिक्षक श्री एस.के. गौतम ने किया। उल्लेखनीय है कि सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर में इस समय एच.डी.सी.एम. सत्र क्रमांक 15 में 23 प्रशिक्षार्थी प्रवेश लेकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

स्व-सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण का जन आंदोलन बनेगा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दिये रणनीति बनाने के निर्देश

भोपाल। प्रदेश में स्व-सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण का जन-आंदोलन बनाया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में बैठक में स्व-सहायता समूहों के सुदृढ़ीकरण के लिये रणनीति बनाने के निर्देश दिये। प्रदेश में वर्तमान में दो लाख से अधिक सक्रिय स्व-सहायता समूह है। बैठक में मुख्य सचिव श्री बी.पी.सिंह उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक में कहा कि स्व-सहायता समूहों के कार्य के लिये नये क्षेत्रों और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुये रणनीति बनाये। स्व-सहायता समूहों के सुदृढीकरण के लिये मिशन मोड में काम करें। इसके लिये लक्ष्य तय करे और रोड मेप बनाये।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत एक लाख 79 हजार, महिला-बाल विकास के तहत 17 हजार तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के तहत 12 हजार स्व-सहायता समूह सक्रिय है। आजीविका मिशन के तहत अनूपपुर, बैतूल और होशंगाबाद जिलों में स्व-सहायता समूहों द्वारा बेहतर कार्य किया गया है। स्व-सहायता समूहों के लिये वस्त्र निर्माण और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। महिला-बाल विकास विभाग की तेजस्विनी योजना के तहत 6 जिलों में स्व-सहायता समूहों द्वारा 11 हाट बाजारों का संचालन किया जा रहा है।

बैठक में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री आर.एस.जुलानिया, प्रमुख सचिव महिला-बाल विकास श्री जे.एन. कन्सोटिया, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विवेक अग्रवाल तथा आजीविका मिशन के संचालक श्री एल.एम. बेलवाल उपस्थित थे।

किसान को उर्वरक की खरीदी हेतु लाना होगा आधारकार्ड

झाबुआ। एक जून से उर्वरक की खरीदी के लिए किसानों को अपना स्वयं का आधारकार्ड लेकर आना आवश्यक होगा। इस नई व्यवस्था के तहत आधारकार्ड होने एवं किसान का अंगूठा लगाने पर ही किसान को खाद मिल सकेगा। उक्त आशय की जानकारी उप संचालक कृषि त्रिवेदी ने किसानों की सहकारी संस्था (इफ्को) द्वारा सहकारी समितियों के प्रबंधक एवं खाद, उर्वरक निजी विक्रेताओं, कृषि विभाग के मैदानी कर्मचारी आदि को दी।

एक जून 2017 से उर्वरक विक्रेताओं के द्वारा पाइंट आफसेल (पास) मशीन के माध्यम से यूरिया, डीएपी एवं एनपीके खाद विक्रय किया जाएगा। ऐसे उर्वरक विक्रेता जो बिना पास मशीन के उर्वरक का विक्रय करेंगे, उनको केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सबसिडी का लाभ नहीं मिलेगा। सहकारी समितियों के प्रबंधक और निजी उर्वरक विक्रेता यह सुनिश्चित करें कि शासन की मंशा के अनुरूप एक जून से किसानों को खाद का वितरण पास के माध्यम से हो।

तकनीकी खामी के बावजूद राशन वितरण नहीं रुकेगा

भोपाल। एनआईसी सर्वर में आयी समस्या के चलते मई माह के राशन वितरण को वितरण पंजी के माध्यम से करने के निर्देश आयुक्त खाद्य द्वारा सभी कलेक्टर्स को दिये गये हैं। खाद्य आयुक्त ने बताया कि तकनीकी खामी के बावजूद राशन वितरण नहीं रुकेगा। मई माह का राशन जिन पात्र उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है, वे राशन की दुकान पर अपने आधार नम्बर की छायाप्रति प्रस्तुत कर राशन प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिये गये हैं कि वह पीओएस मशीन के स्थान पर राशन का वितरण पंजी के माध्यम से करवाना सुनिश्चित करें। नगरीय क्षेत्र में यह व्यवस्था मई माह के लिये की गयी है। नगरीय क्षेत्र में बॉयोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर लागू वितरण व्यवस्था में एनआईसी सर्वर में तकनीकी खराबी के कारण आ रही कठिनाई को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है।

लाड़ली लक्ष्मी योजना की नवीन डोमेन वेबसाइट

भोपाल। लाड़ली लक्ष्मी योजना मध्यप्रदेश शासन की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है। लाड़ली लक्ष्मी योजना की वेबसाइट में नये डोमेन ladlilaxmi.mp.gov.in के माध्यम से डारेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर आनलाईन स्कालरशिप वितरित किया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिए लाड़ली लक्ष्मी योजना के वेबसाईट के डोमेन में परिवर्तन किया गया है। अब लाड़ली योजना की वेबसाइट पुराने डोमेन ladlilaxmi.com के स्थान पर नए डोमेन ladlilaxmi.mp.gov.in के माध्यम से क्रियान्वित होगी।

सोयाबीन किसानों के लिए सामयिक सलाह

रायसेन। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान ने सोयाबीन किसानों के लिए उपयोगी सामयिक सलाह दी है। जारी सलाह में किसानों से कहा गया है कि जिन किसानों ने पिछले दो- तीन वर्षों से खेत की गहरी जुताई नहीं की है, वे गहरी जुताई अवश्य करें। इसके बाद बखर कल्टीवेटर एवं पाटा चलाकर खेत को तैयार करें। किसान दस टन प्रति हेक्टर की दर से पूर्णतर सड़ी हुई गोबर की खाद अथवा ढाई टन प्रति हेक्टर की दर से मुर्गी की खाद का उपयोग अंतिम बखरनी के पहले खेत में करें। अपने क्षेत्र के लिए सोयाबीन की अनुशंसित किस्म का चयन कर बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करें। इन बीजों के अंकुरण का परीक्षण करें। अंकुरण न्यूनतम 70 प्रतिशत होना चाहिये। किसान भाई खाद, खरपतवार नाशक, कीटनाशक, बीज उपचार रसायन, कल्चर आदि की उपलब्धता पहले से सुनिश्चित कर लें। सोयाबीन बीज का भंडारण स्वच्छ, हवादार एवं नमी रहित स्थान पर करें।

समाज के विकास में महिलाओं का योगदान जरूरी

सहकारिता राज्य मंत्री श्री सारंग जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन के कार्यक्रम में

भोपाल। सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने कहा कि समाज के उत्थान में महिलाओं की बराबर की भागीदारी है। राज्य मंत्री श्री सारंग जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन एम.पी. रीजन के शपथ-विधि समारोह को संबोधित कर रहे थे। समन्वय भवन में आयोजित शपथ-विधि समारोह में जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष श्री अभय सेठिया और एम.पी. जोन के चेयरमेन श्री अमर जैन और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

राज्य मंत्री श्री सारंग ने कहा कि समाज को आगे बढ़ाने में जैन समाज द्वारा किया जा रहा संगठित प्रयास सराहनीय है। उन्होंने इस प्रयास में महिलाओं को बराबर की जिम्मेदारी और अधिकार देकर समाज के विकास के लिये काम करने के अवसर प्रदान करने के लिये जैन समाज की सराहना की। श्री सारंग ने फेडरेशन के पदाधिकारियों को शपथ दिलवायी।

राज्य मंत्री श्री सारंग महाराणा प्रताप जयंती पर क्षत्रिय ग्रामीण राजपूत समाज युवा संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि महापुरुषों ने राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देश और समाज को दिये उनके योगदान को हमें याद रखना चाहिये और उनके बताये मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिये। राज्य मंत्री श्री सारंग रवीन्द्र भवन में आयोजित विश्वकर्मा समाज के परिचय एवं चिंतन शिविर में भी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने एक स्मारिका का विमोचन भी किया।

मानव जाति का अस्तित्व बचाने नर्मदा तट पर होगा वृहद वृक्षारोपण

मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा वृक्षारोपण की वेबसाईट का लोकार्पण

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नर्मदा सेवा यात्रा दुनिया में मानव के अस्तित्व को बचाने का महाअभियान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नदियों से वैज्ञानिक तरीके से रेत खनन की व्यवस्था की जायेगी। प्रदेश की खनन नीति को भी बदला जायेगा। रेत के मूल्य को नियंत्रित रखने की व्यवस्था की जायेगी।

श्री चौहान मुख्यमंत्री निवास में नर्मदा सेवा मिशन की वृक्षारोपण में जनभागीदारी के लिये पंजीयन वेबसाईट के लांचिग कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने वेबसाईट का लोकार्पण किया तथा नर्मदा मैया की जय के साथ वृक्षारोपण के लिये उपस्थितों को संकल्पित करवाया। अभियान से जुड़ने के इच्छुक व्यक्ति वेबसाईट पर पंजीयन करा सकते हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पर्यावरण और विकास में संतुलन जरूरी है। निर्माण के लिये रेत के साथ नदियों का अस्तित्व भी जरूरी है। नदियों से सिल्ट उठाने के लिये जितना आवश्यक है, उतना ही उत्खनन हो। ऐसे प्रबंध किये जायेंगे। मशीनों से रेत उत्खनन पूर्णत: बंद किया गया है। उत्खनन पर खनिज निगम का नियंत्रण होगा। वही उसका मूल्य भी निर्धारित करेगा ताकि गरीबों को मकान बनाने के लिये सस्ती दर पर रेत की आसान उपलब्धता हो। ठेके से रेत उत्खनन व्यवस्था को बदला जायेगा। उत्खनन कार्य मजदूरों से होगा। महिलाओं और युवाओं के स्वसहायता समूह ही उत्खनन करेंगे, जिनको माइनिंग कार्पोरेशन रेत के विपणन से होने वाला लाभांश बोनस के रूप में देगा। इससे उत्खनन से मिलने वाला पैसा जो अभी चंद ठेकेदारों की जेब में जाता है, वह लाखों गरीब मजदूर परिवारों को मिलने लगेगा।

उन्होंने कहा कि नर्मदा सेवा मिशन के तहत हर वर्ष वृहद वृक्षारोपण किया जायेगा। आगामी दो जुलाई को नर्मदा के तट और संपूर्ण कैचमेंट एरिया में वृक्षारोपण किया जायेगा। वन, राजस्व भूमि में वन प्रजाति और निजी भूमि पर फलदार पौधे लगाये जायेगें। पेड़ों को जिंदा रखने के सभी जरूरी कार्य किये जायेंगे। इसके साथ ही ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर मल-जल को नर्मदा की विपरीत दिशा में ले जाया जायेगा। उसे रि-सायकल कर बागानों, खेतों आदि में छोड़ा जायेगा। धर्म-प्रमुखों ने पूजन-विधि भी बदली है। पूजन-सामग्री विर्सजन के कुंड भी बन रहे है। जैविक खेती को बढ़ाया जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नर्मदा सेवा अभियान को अन्य नदियों पर भी लागू किया जायेगा। इसे पर्यावरण के अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि अभियान जनता का है, उसे ही आगे रहना होगा। अभियान में सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि नदी पर्यावरण संरक्षण के इस महायज्ञ में आहूति देने के लिये आगे आयें। मुख्यमंत्री ने जन-जागृति की अलख जगाने का आव्हान किया तथा कहा कि आगामी दो जुलाई को पौधरोपण करने वालों का ऐसा मेला लगे, जिसे देख देश-दुनिया चमत्कृत हो जाये। उन्होंने कहा कि नर्मदा सेवा मिशन धरती को बचाने का अभियान है। धरती का जिस तेजी से तापमान बढ़ रहा है, उसे यदि नियंत्रित नहीं किया गया तथा चंद भौतिक सुविधाओं के लिये प्रकृति के साथ अंधाधुन्ध छेड़छाड़ नहीं थमी तो, यह भविष्य की पीढ़ी के लिये कब्र खोदने जैसा होगा।

इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह के साथ नर्मदा सेवा मिशन के प्रथम स्वयं सेवक के रूप में http://www.namamidevinarmade.mp.gov.in पर पंजीयन करवाया।

ग्रामीण आजीविका मिशन में महिलाएँ बना रही हैं गमछे और टी-शर्ट

भोपाल। ग्रामीण महिलाएँ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूहों से जुड़कर न केवल सिलाई प्रशिक्षण प्राप्त कर रहीं है बल्कि उनके द्वारा तैयार किये गये गमछे एवं टी-शर्ट से उन्हें अतिरिक्त आय का जरिया मिल गया है। ग्रामीण गरीब महिलाओं को इसका सीधा फायदा मिलने से उन्हें बिचौलियों से भी निजात मिल गई है।

प्रदेश के पाँच जिला बड़वानी,राजगढ़, सागर,छतरपुर एवं शिवपुरी जिले की 540 महिलाओं ने कम समय एवं कम खर्च पर ड़ेढ़ लाख गमछे एवं एक लाख टी-शर्ट तैयार की हैं। स्वच्छ भारत मिशन द्वारा चिन्हित किये गये उत्कृष्ट ग्रामीण स्वच्छता दूतों को अपने- अपने क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य के एवज में ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार किये गये गमछे एवं टी-शर्ट से सम्मानित किया जायेगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के राज्य कार्यक्रम अधिकारी के समक्ष यह चुनौती थी कि गमछे एवं टी-शर्ट कम समय एवं कम खर्चे पर कैसे तैयार करवाई जायें। यह काम सौंपा गया मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की गठित स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी गरीब महिलाओं को।

ग्रामीण आजीविका मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एल.एम. बेलवाल ने बताया कि 33 जिलों में ग्रामीण आजीविका मिशन से 1 लाख 79 हजार स्व-सहायता समूहों के माध्यम से 20 लाख 67 हजार परिवार जुड़ चुके हैं। इन स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को उनकी रुचि एवं क्षमता अनुरूप काम करने के लिए दक्षता संवर्धन प्रशिक्षण के बाद काम शुरू करने के लिए आवश्यक उपकरण,कच्ची सामग्री के लिए आर्थिक मदद भी दी जाती है। सामान्य तौर पर महिलाओं के लिए सिलाई का काम सहज एवं रुचिकर होता है। इसलिए आसेटी एवं एन.आई.एफ के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण दिलवाया जाता है।

घुमक्कड जनजाति विकास हेतु योजनाएं संचालित

उज्जैन। विमुक्त घुमक्कड अर्द्धघुमक्कड जनजाति विकास हेतु मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में विमुक्त घुमक्कड अर्द्धघुमक्कड जनजाति के हितग्राही सदस्यों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराये जाने हैं। उज्जैन जिले को 20 हितग्राही को ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत 50 हजार से अधिकतम 10 लाख तक ऋण दिये जाने का प्रावधान है। तीन प्रतिशत मार्जिन मनी अधिकतम दो लाख रूपये तक होगी। इस योजना के लिये विमुक्त घुमक्कड अर्द्धघुमक्कड जनजाति का सदस्य होना एवं सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है। आवेदन का प्रारूप एवं अन्य जानकारी शासकीय अवकाश को छोडकर कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।

चालक को स्वयं सावधानीपूर्वक वाहन का करना होगा उपयोग

पीटीआरआई में सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन पर सेमीनार का समापन

भोपाल। सड़क शहर की धमनी होती है, इसे क्लियर रखना बहुत जरूरी है। रोड जाम होने से शहर थम जाता है। पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान में सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन पर सेमीनार के दूसरे दिन यह बात चीफ सिक्यूरिटी कमिश्नर दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन श्री मुकुल उपाध्याय ने कही।

उन्होंने कहा कि व्यक्ति को दूसरे लोगों को अज्ञान समझकर गाड़ी चलानी चाहिये। वाहन चालक को स्वयं सावधानीपूर्वक वाहन का उपयोग करना चाहिये, इससे सड़क दुर्घटना में कमी आयेगी। श्री उपाध्याय ने कहा कि वाहन का हेल्थ चेक-अप समय-समय पर करवाना अति-आवश्यक है। कई बार गाड़ी की सर्विसिंग नहीं करवाना भी दुर्घटना का कारण बनता है। वाहनों की संख्या पर नियंत्रण भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सिंगापुर में अगर घर में पार्किंग की जगह नहीं है तो वाहन खरीदने की परमीशन नहीं मिलती। ट्रेफिक मैनेजमेंट के लिये नया कानून लाना होगा। इसमें पैदल चलने वाले व्यक्ति, रिक्शा-चालक आदि को भी कानून के दायरे में लाना होगा।

श्री उपाध्याय ने कहा कि मोटर वाहन के कारण 25 से 30 प्रतिशत क्राइम होता है। इसमें गाड़ी चोरी, दुर्घटना और पार्किंग के कारण लड़ाई-झगड़ा होना आदि शामिल है। उन्होंने कहा कि दूसरे मुल्कों में सड़क का उपयोग व्यक्ति और वाहन द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ इसका विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाता है, जैसे पार्किंग, सामान बेचने वाले ठेले आदि। उन्होंने बताया कि जल्द ही नया एक्ट आने वाला है। इसमें 4 साल के बच्चों और महिलाओं को भी हेलमेट अनिवार्य किया गया है। एक्ट में कड़े प्रावधान किये जायेंगे। ट्रेफिक सिग्नल तोड़ने, स्टॉप-लाइन के बाहर जाने आदि पर भी चालान होगा। नियम तोड़ने वालों का लायसेंस 3 माह के लिये सस्पेंड किया जायेगा। श्री उपाध्याय ने बताया कि आने वाले समय में टेक्नालॉजी का उपयोग इतना बढ़ेगा कि ड्रिंक कर वाहन में बैठने पर सेंसर के जरिये अल्कोहल की स्मेल के कारण वाहन स्टार्ट ही नहीं होगा। जब तक चालक सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करेगा, उस समय भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पुलिस का काम रेवेन्यू कलेक्शन नहीं है। यातायात नियमों का पालन करवाना और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई का दायित्व पुलिस का है। उन्होंने कहा कि आम आदमी को नियम को धर्मग्रंथ के रूप में लेना चाहिये। नागरिक नियमों का ज्ञान नहीं होने पर भी कानून तोड़ते हैं। चौराहे पर मोटर व्हीकल एक्ट सभी के लिये है।

श्री उपाध्याय ने बताया कि जुलूस, जलसा, व्हीआईपी भ्रमण के समय बंद होने वाले रास्ते और परिवर्तित मार्ग का व्यापक प्रचार-प्रसार पहले से ही किया जाना चाहिये। इससे आम आदमी खुद-ब-खुद असुविधा से बचने के लिये उस जगह से नहीं जायेगा। कम से कम ट्रेफिक को रोका जाये, जिससे जाम की स्थिति न बने और व्हीआईपी के चौराहे से निकलने के तुरंत बाद ट्रेफिक को छोड़ा जाये।

फॉरेन्सिक एक्सपर्ट डॉ. शैली लुकोस ने बताया कि सड़क दुर्घटना की जाँच करते समय पुलिस को क्या-क्या करना चाहिये। उन्होंने दुर्घटना-जाँच के स्तर के विभिन्न घटक की जानकारी दी। सबूत के तौर पर टॉयर मार्क्स, फिंगर प्रिंट्स आदि पर भी ध्यान देने को कहा। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना के समय 72 प्रतिशत प्रकरण में हेवी व्हीकल के ड्रायवर की गलती मानी जाती है।

मिट्टी परीक्षण में मध्यप्रदेश देश में छठवें स्थान पर

अनूपपुर। प्रदेश शासन के कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने जिला मुख्यालय अनूपपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश एवं केन्द्र सरकार के सहयोग से मध्यप्रदेश सन् 2022 तक कृषि उत्पादन को दुगना करने में सफल होगा। आपने बताया कि पंडित दीनदयाल जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में प्रदेश सरकार द्वारा 14 अप्रैल डॉ. अम्बेडकर जयंती से कृषि महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस दौरान गांव-गांव में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को उन्नत बीज, मिट्टी परीक्षण के लाभ, लाईन से बुवाई, पानी का बेहतर उपयोग, फसल चक्र, जैविक खेती आदि की जानकारी दी। आपने बताया कि मिट्टी परीक्षण के क्षेत्र में मध्यप्रदेश गत वर्ष 26वें स्थान पर था, जहां से 20 पायदान उछाल मारते हुए इस वर्ष 6वें स्थान पर आ गया है।

आपने बताया कि प्रदेश के हर ब्लाक में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालायें जून माह तक संचालित कर दी जाएगी। राज्य सरकार ने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान का नारा दिया है। खेती की लागत को कम करने तथा किसानों की आय दुगनी करने हेतु यंत्रीकरण, परम्परागत खेती का आधुनिकीकरण, उत्पादित अनाज को बाजार दिलाने, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही एग्रो, फारेस्ट्री के माध्यम से भी आय बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में उन्नत बीज बदलाव, कम बीज, कम पौधों से अधिक उत्पादन, नरवाई पर रोक, जीरो ट्रिलर के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया है। अब सरकार भूसा पर भी अनुदान देने पर विचार कर रही है।

कपास उत्पादक किसानों को बड़ी राहत

कम कीमत पर कपास बीज के लिये मंत्री श्रीमती चिटनिस की पहल

भोपाल। महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस की पहल से प्रदेश के कपास उत्पादक किसानों को बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें नान बी.टी. कपास बीज भारत सरकार द्वारा निर्धारित कीमत पर उपलब्ध होगा।

उल्लेखनीय है कि बुरहानपुर, खरगोन तथा बड़वानी के कपास उत्पादक किसानों से नान बी.टी. कॉटन बीज की कालाबाजारी की शिकायतें लगातार मिल रही थी। उन्हें महाराष्ट्र की तुलना में तीन गुना अधिक कीमत पर यह बीज लेना पड़ता है। इस संबंध में किसानों ने जिला और राज्य स्तर पर अपनी समस्याएँ रखी थीं।

मंत्री श्रीमती चिटनिस ने मंत्री परिषद की बैठक में यह मामला उठाने के साथ-साथ किसान कल्याण विभाग को भी इस दिशा में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा था। परिणामस्वरूप किसान कल्याण विभाग ने प्रकरण को संज्ञान में लिया। प्रदेश के कपास उत्पादक सभी जिलों के बीज व्यापारियों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार ही बीज विक्रय के निर्देश दिये गये। संबंधित जिला कलेक्टर्स को भी बीज का विक्रय निर्धारित मूल्य पर करवाने के लिए निर्देशित किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान से सहकार भारती के प्रतिनिधि मंडल की सौजन्य भेंट

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से यहां निवास पर सहकार भारती के प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की।प्रतिनिधि मंडल में श्री विजय देवांगन, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, श्री उदय जोशी, राष्ट्रीय महामंत्री, श्री विवेक चतुर्वेदी, प्रदेश महामंत्री सहकार भारती, चौधरी नारायण सिंह, महाकौशल प्रांत महामंत्री, श्री धर्मेन्द्र पटेल, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक जबलपुर उपस्थित थे।

सीहोर जिले के आदिवासी बहुल ग्रामों में मुख्यमंत्री द्वारा दो सिंचाई योजनाओं को मंजूरी

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के प्रवास के दौरान दो लघु सिंचाई परियोजना को स्वीकृत किया। नसरूल्लागंज विकास खंड के ग्राम महादेव बेदरा में उन्नीस करोड़ तीस लाख रू. लागत की इस परीयोजना के पूरा होने पर 1200 एकड़ में सिचाई होगी। इसी प्रकार अमीरगंज तालाब से सिंचाई परियोजना को भी स्वीकृत कर तत्काल कार्य आंरभ करने के निर्देष सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दिये। ग्यारह करोड़ पैंसठ लाख रू. लागत की इस सिंचाई परियोजना में करीब 750 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दोनों सिंचाई योजनाओं की मांग ग्रामीणों द्वारा काफी लम्बे समय से की जा रही थी। जनता से बातचीत करते हुए श्री चौहान ने कहा कि पलास पानी और पातल पर्ट तलाई योजनाओं का ससर्वे कराया जा रहा है। उन्होनें सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये स्वीकृत योजनाओं का निर्माण कार्य शीध्र शुरू हो ताकि किसान के खेत तक पानी जल्द पहुँचे। जो गॉव रह गये है, उनमें भी जल्द ही सिंचाई सुविधा पहुॅचाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्राम अमीरगंज भैसान में आयोजित किसान सम्मेलन में कहा कि आगामी 1 जून को भोपाल में ग्लोबल स्किल डवलापमेंट समिट आयोजित की जाएगी। जिसमें युवाओं को तकनीकी क्षेत्र में रोजगार देने वाली बडी बडी कम्पनीयों के प्रतिनिधि आकर प्रदेश के युवाओ को आत्म निर्भर बनाने हेतु रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर चर्चा करेंगें। तथा युवाओं का मार्गदर्शन देंगें। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नर्मदा तट पर 2 जुलाई को करोड़ों पौधे रोपित किये जाएगें। उन्होने स्थानीय ग्रामीणो से अपील की कि वे भी वृक्षा रोपण महाअभियान में पौधरोपण कर अपनी भागीदारी दें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर लोक स्वास्थ यांत्रिक विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि नसरूल्लागंज क्षेत्र के जिन गॉव मे पेय जल समस्या हो वहॉ पानी कि टंकी बनवाने कि व्यवस्था करें ताकी नर्मदा का जल गॉव गॉव मे पाईप लाईन के माध्यम से घर घर तक पहुँचाने की व्यवस्था की जा सके। उन्होने आमीर गंज में हायर सेंकडरी स्कूल, पशुचिकित्सलय, यात्री प्रतिक्षालय, व स्टीट लाईट स्वीकृत करने की घोषण भी कि।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर कहा कि किसी को भी आवास हीन व भूमि हीन नही रहने दिया जायेगा। हर गरीब परीवार के लिये आवासीय भूमि और भवन कि व्यवस्था सरकार कर रही है उन्होंने कहा कि खेती को लाभ का घंधा बनाने और अगले 5 वर्षों में किसानो की आय दुगनी करने के लिये सरकार प्रयास कर रही है। उन्होने कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि नसरूलागंज क्षेत्र के आदिवासी बहुल गॉवो मे कृषि उत्पादन व आय बढाने के लिये अलग से विशेष योजना तैयार करें।

गत दिवस क्षेत्र के ग्राम मोगराखेडा में जिन 3 आदिवासी जयराम वारेला, कीर्तिसिंह बारेला, और भारत सिंह के घर जल गये थे उन्हे एक लाख चार हजार रू. राहत राषि के चेक प्रदान किये उन्होने बालिका कु. रिंकी व प्रतिभा के लाडली लक्ष्मी योजना के तहत प्रमाण पत्र प्रदान किये।

कार्यक्रम में मार्कफेड अध्यक्ष श्री रमाकांत भार्गव, वन विकास निगम अध्यक्ष श्री गुरू प्रसाद शर्मार्, वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह राजपूत, म.प्र. बाल आयोग सदस्य श्रीमती निर्मला, बारेला, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला मरेठा जन प्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारियों सहित बडी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे। इसके पूर्व मुख्यमंत्री ग्राम आमाडोह मे आयोजित किसान सम्मेलन भी शामिल हुए।

नरवाई जलाने वाले किसान से प्रतिबंधित पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूली होगी

भोपाल। पर्यावरण सुरक्षा, जन-स्वास्थ्य एवं जीव-जन्तुओं के जीवन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पर्यावरण प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम-1981 के तहत प्रदेश में धान एवं गेहूँ की फसल की कटाई के बाद फसल अवशेषों (नरवाई) को जलाना प्रतिबंधित किया गया है।

ट्रिब्यूनल के निर्णय के अनुसार राज्य के पर्यावरण विभाग ने इस संबंध में सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने के बाद किसान-कल्याण एवं कृषि विकास विभाग ने सभी कलेक्टर्स को अधिसूचना के निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश जारी कर दिया है।

विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अधिसूचना के निर्देश के अनुरूप कार्यवाही का दायित्व जिला दण्डाधिकारी का निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर व्यक्ति या निकाय को पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि देय होगी। इसके अनुसार दो एकड़ से कम कृषि भूमि वाले किसान से नरवाई जलाने पर 2500 रुपये, दो से अधिक एवं पाँच एकड़ से कम कृषि भूमि वाले किसान से नरवाई जलाने पर 5 हजार रूपये एवं पाँच एकड़ से अधिक कृषि भूमि वाले किसान से 15 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूली जायेगी। उल्लेखनीय है कि नरवाई जलाने से पर्यावरण प्रदूषण के साथ-साथ पशु-पक्षियों की जान का खतरा होता है। कभी-कभी मानव हानि भी होती है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति, सूक्ष्म जीवाणु एवं आर्दता खत्म होने से फसल की उत्पादकता भी कम होती है।

मध्यप्रदेश में पॉलीथिन प्रयोग प्रतिबंधित अधिसूचना जारी

भोपाल। राज्य शासन ने लोकहित में सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। पॉलीथिन पर प्रतिबंध मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम 2004 को संशोधित करते हुए मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम 2017 के तहत किया गया है।

पहाड़ पर बसे गाँव में सड़क बनने से परिदृश्य बदला

भोपाल। अब उस गाँव में शादियाँ आसानी से होने लगी है। प्रसव के दौरान होने वाली मौतों का सिलसिला थम गया है। बीमार होने पर ग्रामीण अब वाहन से अस्पताल जाने लगे हैं। गाँव में अब एक फोन पर जननी एक्सप्रेस आ रही है। लोगों ने 4-5 मोटर साइकिल भी खरीद ली है। जी हाँ, यह उपलब्धि है दमोह जिले के जबेरा विकासखण्ड में पहाड़ी पर बसे ग्राम बोदा मानगढ़ की। एक साल पहले ही ग्राम पटी से बोदा मानगढ़ सड़क बन जाने से गाँव में 12 मासी आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो गई है।

यह सब संभव हुआ मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से। इसके फलस्वरूप 99 लाख रूपये की लागत से पहाड़ को काटकर बनाई गई सड़क से आवागमन की राह आसान हुई, साथ ही ग्राम की उन्नति के दरवाजे भी खुल गये हैं।

ग्राम बोदा के बुजुर्ग श्री प्रताप सिंह कहते हैं सरकार जो कहती है, वह करती है। ऐसी सरकार सदा बनी रहे। उनका कहना है कि गाँव के लोग पहले पहाड़ से करीब 2 किलोमीटर पगडंडी से पटी और सिंग्रामपुर-जबेरा जाते थे। गाँव में लोग लड़की नहीं देते थे, मुश्किल से शादी होती थी और बीमार हुए तो मरीज को ले जाना बड़ा मुश्किल होता था।

गाँव में 40-45 घर आदिवासी के हैं। अब वे सब गाँव में सड़क बन जाने से बेहद खुश हैं। ग्राम के श्री इमरत का कहना है कि सड़क क्या बनी हमें विकास की नई दिशा मिल गई। गाँव में स्कूल भवन बना है और हाल ही में सामुदायिक भवन का भूमि-पूजन भी हुआ है।

ग्रामवासियों का कहना है कि 3 हेण्ड-पम्प हैं। गाँव में बिजली है और इस संबंध में उन्हें कोई शिकायत नहीं है। जब तालाब की मांग के संबंध में सीईओ, जिला पंचायत श्री अशोक कुमार ओहरी को बताया गया तो उन्होंने तत्काल ही अगले दिन काम शुरू करवाया और कहा कि दूरस्थ दुर्गम गाँव में और जो भी संभव होगा, करवाया जायेगा।

विकलांगजनों के लिए बनेंगे विशिष्ट पहचान पत्र

सीहोर। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक नि:शक्तजन को यूनिक आईडी कार्ड दिए जाने के उद्देश्य से यू डी आई डी पोर्टल लांच किया गया है। यह परियोजना विकलांगजनों के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने और प्रत्येक विकलांगजन को एक विशिष्ट विकलांगता पहचान-पत्र जारी करने के उद्देश्य से कार्यान्वित की जा रही है। यह परियोजना केवल पारदर्शिता, कार्यकुशलता तथा विकलांगजनों को सरकारी लाभ प्रदान करना सुगम ही नहीं बनाती हैं बल्कि यह सार्वभौमिकता भी सुनिश्चित करती है। यूनिक आईडी कार्ड परियोजना ग्राम स्तर, ब्लाक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक कार्यान्वन के सभी स्तरों पर लाभार्थी की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी को सुप्रभावी बनाने में भी सहायता करेगी। शासकीय कार्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों एवं संस्थाओं में जो भी नि:शक्त अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं, वे संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के कार्यालय में उपयुक्त अभिलेख जमा कर यूनिक आईडी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।

“लू से सावधानी, थोड़ा ज्ञान, बचाये सबकी जान”

“लू के प्रभाव से प्रदेशवासियों के बचाव हेतु हम प्रयासरत हैं। सभी प्रदेशवासियों से अपील है कि आप लू के प्रभाव को गंभीरता से लेते हुये इससे बचाव हेतु आवश्यक सावधानी अपनाकर निरोगी एवं सुरक्षित रहें।”

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

निम्नलिखित सावधानियाँ बरतें :-

- समाचार पत्र, रेडियो एवं टेलीविज़न के माध्यम से स्थानीय मौसम की जानकारी रखें।
- पानी, छांछ, ओ.आर.एस. का घोल या घर में बने पेय जैसे:- लस्सी, नींबू पानी, आम का पना इत्यादि का सेवन कर तरोताजा रहें।
- सूती, ढीले एवं आरामदायक कपड़े पहनें। सिन्थेटिक अथवा गहरे रंग के वस्त्र पहनने से बचें।
- धूप में निकलते समय अपना सिर ढंककर रखें। कपड़े, टोपी अथवा छतरी का उपयोग करें।
- यथा संभव दोपहर 12 से 3 बजे धूप में बाहर निकलने से बचें।
- जानवरों को छाया में रखें और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी दें।
- बच्चों अथवा पालतू जानवरों को वाहनों में छोड़कर न जाएं - उन्हें लू लगने का खतरा हो सकता है।

श्री शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

धूप में निकलने के पूर्व तरल पदार्थ का सेवन करें।
पानी हमेशा साथ में रखें। जलयोजित रहें,
शरीर में पानी की कमी नहीं होने दें।

लू के लक्षण

सिरदर्द, बुखार, उल्टी,
अत्याधिक पसीना एवं
बेहोशी आना,
कमजोरी महसूस होना,
शरीर में ऐंठन,
नब्ज असामान्य होना।

लू के लक्षण हों,
तो प्रभावित को तत्काल
नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र
पर ले जाकर
चिकित्सकीय परामर्श लें।

आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2017

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन

Follow us on @mpsdma @mpsdma
Visit: www.mpsdma.mp.gov.in

D-81257/2017

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा सांध्य प्रकाश लि.'सांध्यप्रकाश भवन' मालवीय नगर, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2015-17 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।